

सरकार को जिला बनाने के पूर्व पुनर्गठन करवाना था-पटेल

अगली सरकार हमारी बनी तो विसर्गितियों को दूर करना लक्ष्य

छत्तीसगढ़ संवाददाता अंबिकापुर, 8 फरवरी। बुधवार 8 फरवरी को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार पटेल अंबिकापुर प्रवास के दौरान स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जिले का विभाजन जिस प्रकार से की है, वह जनभावनाओं के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। जिस पर जनता द्वारा किए गए दावा आपत्ति के बावजूद सरकार पहल करना भी उचित नहीं समझी। सरगुजा के संदर्भ में भी सरकार ने ऐसा किया है।

प्रदेशाध्यक्ष पटेल ने बताया कि जिले का सामरी एवं वाडफुनगर क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित हुआ है। यहां की जनता को किसी भी कार्य के लिए, 100 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था। अब भी पड़ेगा जिसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। सरकार को नवीन जिला

बनाने से पूर्व सरगुजा को भौगोलिक स्थितियों एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शामिल करना था। ताकि का हक बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश चिन्हित क्षेत्रों में ही विकास के बहाने धन खर्च कर रही है जबकि



आमजनता को परेशानी ना हो लेकिन सरकार को इससे कोई लेनादेना नहीं। वह जिला निर्माण जनभावना के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए की है।

नंदकुमार पटेल ने छत्तीसगढ़ शासन को मिलने वाले 36 हजार करोड़ के बजट में पूरे प्रदेश का बराबर

कई क्षेत्र अभी तक विकास को बांट जोर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास की धन राशि प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास के लिए खर्च की जानी चाहिए, जिसका उदाहरण देते हुए पटेल ने शंकरगढ़ एवं कुसमी क्षेत्र को विकास की किरणों से कोसों दूर बताया।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में आमजनों के हितों के मध्य श्री पटेल ने सरगुजा एवं बस्तर के लोगों को मंत्रालय संबंधी कार्यों के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटेल ने सरगुजा जिले में निर्माण कार्यों के बारे में बताया कि जिले में पंचायत स्तर से जिला स्तर के द्वारा कराया गया कार्य गुणवत्ताविहीन है, सड़क बने रहे लेकिन डामर का नामो निशान नहीं है, नहर का निर्माण उसदा गया है लेकिन पानी का ठहराव ही नहीं कुशरोपण के नाम पर करोड़ों की राशि का बंधाधार किया गया। लेकिन युवा का अला पता ही नहीं। श्री पटेल के पत्रकारों को बताया कि सरकार आर हमारी 2013 में आई तो सरगुजा के सारे विसर्गितियों को 2 वर्ष के भीतर ही दूर कर विकास करके दिखा देंगे।

समितियों में नहीं पहुंचे बारदाने, किसान परेशान

छत्तीसगढ़ संवाददाता जांजगीर-चांपा, 8 फरवरी। धान खरीदी में किसानों को तमाम सुविधाएं देने के दावे की पोल खुलने लगी है। खरीदी केन्द्र में बारदाना नहीं होने से पिछले 25 दिनों से किसान धान बेचने के लिए परेशान हैं। प्रशासन व विपणन संघ के अधिकारी पर्याप्त संख्या में बारदाने उपलब्ध होने का दावा कर रहे हैं, उसके बावजूद खरीदी केन्द्रों में बोरे नहीं पहुंचना जांच का विषय है। इस संबंध में मालखरीदा क्षेत्र के ग्राम पिरदा के लगभग 50 किसान कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे थे।



25 दिनों से नहीं खरीदी गई धान

जिले में शासन की नीतियों के तहत किसानों से धान खरीदी किया जाना सुनिश्चित है। किसानों को खरीदी केन्द्रों में सुविधाएं दिलाने के लिए कई योजनाएं भी हैं। लेकिन सभी नियमों के बावजूद धान बेचने पहुंचे किसान खास परेशान हैं। बारदाने की कमी से जिले के कई खरीदी केन्द्रों में अव्यवस्था का

भी हो रहा है। आगामी कुछ दिनों बाद शासन के आदेशानुसार धान खरीदी बढ़ कर दी जाएगी तो हम कहां अपना धान बेचेंगे ?

इस मामले में अपर कलेक्टर बिपिन मांझी का कहना है कि बारदाने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, पिरदा खरीदी केन्द्र में बोरे क्यों नहीं पहुंचे, इसकी जांच व तत्काल बारदाने उपलब्ध कराने के निर्देश हमने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं, जल्द ही किसानों की समस्या हल हो जाएगी।

विवि में एनएसयूआई का प्रदर्शन



अंबिकापुर, 8 फरवरी। 18 फरवरी को एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सचिन जायसवाल के नेतृत्व में सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। कहा गया कि विश्वविद्यालय के अभी तक कई कक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना व पुरक परीक्षाओं के परिणाम नहीं आए हैं। वहीं प्रायवेट परीक्षाओं के फार्म भी अभी तक बंटना प्रारंभ नहीं किया गया है।

इस संबंध में एनएसयूआई अध्यक्ष सचिन जायसवाल ने बताया कि सरगुजा एक ग्रामीण व पिछड़ा क्षेत्र है यहां दूर-दराज से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं परन्तु सरगुजा विश्वविद्यालय की ऐसी दूरदर्शा है कि यहां की लचर व्यवस्था से सरगुजा के समस्त छात्र हमेशा से ही परेशानियों का सामना करते रहे हैं। इन्हीं सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिव का धेराव किया गया व जमकर उनके विरोध में नारेबाजी की गई जहां नारेबाजी के पश्चात कुलसचिव ने बाहर आकर छात्रों से मिले व प्रायवेट फार्म एक सप्ताह के अन्दर बंटवाने का आश्वासन दिया व साथ ही पुरक परीक्षा तथा पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किये जाने का आश्वासन दिया।

बरमकेला क्षेत्र में नक्सली आहत, ग्रामीण खौफ में

छत्तीसगढ़ संवाददाता रायगढ़, 8 फरवरी। बरमकेला विकासखण्ड मुख्यालय होने के बाद भी यहां फैले सन्नाटा से स्पष्ट हो रहा है कि क्षेत्र नक्सलियों के भय से ग्रसित है। बरमकेला दानव करवट वन महानदी किनारे शुरू होकर महासमुंद्र जिला से होते हुए उड़ीसा तक फैला हुआ है। जहां पहले लोग शांति से चहल कदमी करते नजर आते थे, वहीं यह शांत क्षेत्र अब नक्सलियों के खौफ से अशांत हो चुका है। परधियापाली, करामाल, करपी, सुअरगुड़ा गोमर्डी क्षेत्र के बाद अब बरमकेला मुख्यालय में दक्षिण भाग में फैले जंगल में नक्सलियों को आहत सुनाई देने लगी है। बरमकेला थाना मुख्यालय से मात्र तीन किलोमीटर दूर पठियापाली के आसपास नक्सलियों को देखे जाने की चर्चा है। इसी के साथ भुकरा के क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से नक्सली आमद की सूचना के बाद जिला पुलिस बल तथा एस.टी.एफ.के जवानों ने तत्काल सर्चिंग शुरू

कर दी है। इस सर्चिंग का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक डॉ. आनंद छाबड़ा स्वयं ही कर रहे हैं। 27 जनवरी को एक नक्सली के मारे जाने के बाद से क्षेत्र में वैसे ही भय का माहौल है। लोगों को आशंका है कि लाल आंतक बदला लेने के लिये कहीं बड़ी बारदात को अंजाम देने की फिाक में है। पठियापाली, भुकरा, आमाकोनी, दादरपाली, कुधरगढ़ी जैसे शांत गांव में भी अब नक्सलियों की आहत से भय व्याप्त है। कुछ दिन पूर्व ही गृह मंत्री ननकराम कंवर ने जिला पुलिस बल की जम कर सराहना की है। पुलिस अधीक्षक डॉ. आनंद छाबड़ा के रहते बरमकेला पुलिस विकासखण्ड में लाल आंतक निश्चित ही किसी बड़े अंजाम को देने में नाकाम साबित होंगे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बरमकेला से एस.टी.एफ. तथा पुलिस जवानों ने सर्चिंग शुरू कर भुकरा होते हुए आगे की कार्रवाई जारी रखी है। माने तो नक्सली मुठभेड़ में 27 जनवरी को एक नक्सली के मारे जाने के बाद से नक्सली कई गुप में बंट चुके हैं।

बाहुबलियों ने जनप्रतिनिधि को पीटा

सोनहत, 8 फरवरी। विकासखण्ड मुख्यालय में सोमवार की शाम लगभग बाहुबलियों का आतंक सलगवांकला के जनप्रतिनिधि उपसरपंच रामप्रताप राजवाड़े पर कहर बनकर टूटा। घटना से आहत जनप्रतिनिधि ने भयवश रात में लगभग 11 बजे थाना पहुंचकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराते हुए मुख्यालय में चल रहे आंतकी माहौल से जनप्रतिनिधियों को निजात दिलाने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई।

घटना के संबंध में आहत उपसरपंच रामप्रताप ने बताया कि विगत दिवस पंचायत स्तर पर विभिन्न अनियमितताओं, रोजगार गारंटी के मजदूरी भुगतान एवं ठेकेदारी से सीसी रोड निर्माण कार्य की जांच हेतु आवेदन कलेक्टर कारिया को 31 जनवरी को दिया गया जिसकी जांच 7 दिवस में कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा 6 फरवरी को जांच दल भेजा गया। जांच के बाद मजदूरों को लेकर जनपद आ रहे उपसरपंच को मजार चौक के पास तथाकथित बाहुबलियों द्वारा विवाद करते मारपीट कर दिया। घटना से आहत जनप्रतिनिधि द्वारा भयवश रात में थाने पहुंच संबंधित घटना की लिखित जानकारी देकर कार्यवाही किए जाने की मांग की।

जनप्रतिनिधि संगठित मुख्यालय स्तर पर जनप्रतिनिधि

उपसरपंच रामप्रताप राजवाड़े के साथ हुए कथित अमानवीय कृत्य को गंभीरता से लेते हुए खण्डस्तर पर जिला, जनपद एवं पंचायत के प्रतिनिधियों ने आगामी दिनों में बैठक आहूत किए जाने का संकेत देते हुए पूरे घटना पर उच्च स्तरीय कार्यवाही किए जाने आंदोलन किया जाना प्रस्तावित कर दिया है।

उपसरपंच के साथ पूरा पंचायत विकासखण्ड मुख्यालय में मजदूर हित से जुड़े मामले पर उपसरपंच द्वारा किए जा रहे सकारात्मक प्रयास के बदले बाहुबलियों द्वारा मारपीट किए जाने के परिपेक्ष्य में पूरा खण्ड स्तर पर उपसरपंच के साथ पंचायत प्रतिनिधि एक साथ खड़े हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार केसगांवां, बैलिया, रजौली, भेंसवार, सलगवां, मेण्ड्रा, सिधोर नटवाही, रामगढ़ के सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने मामले को लेकर एक स्वर में सहयोग किया जाना बताया है।

बाहुबलियों के आंतक से छुटकारा दिलाने की मांग मुख्यालय स्तर पर विगत लंबे समय से आए दिन किसी जांच अथवा अपने ठेकेदारी को बढ़ावा देने अधिकारी-कर्मचारी से लेकर जनप्रतिनिधियों पर किए जा रहे अशुभ व्यवहार से लेकर मारपीट किए जाने का पूरे ग्रामजनों ने गहरा खेद व्यक्त किया है।

कलेक्टर के दस्तखत को फर्जी बता रही सरपंच वनभूमि के पट्टे से बेदखल करने पर अड़ा




छत्तीसगढ़ संवाददाता जांजगीर-चांपा, 8 फरवरी। साढ़े तीन वर्ष पूर्व शासन की योजना के तहत वनभूमि पर दिए गए पट्टे को ग्राम चंदनिया की महिला सरपंच मानने को तैयार नहीं हैं, पट्टे पर मिली जमीन पर सरपंच तालाब खुदाई कराने के लिए अड़ी हुई हैं। उसने शासन द्वारा दिए गए पट्टे में किए गए कलेक्टर के हस्ताक्षर को फर्जी कहकर हितग्राहियों को उरु जमीन खाली करने की हिदायत दी है। सरपंच की मनमानी से त्रस्त होकर पट्टाधारी हितग्राही कलेक्टरों पहुंचे, जहां अपर कलेक्टर से मिलकर मामले की शिकायत की है।

अकलतरा विकासखंड के ग्राम चंदनिया के 9 ग्रामीणों को शासन की योजनानुसार 15 अगस्त 2008 को अकलतरा में एक कार्यक्रम के दौरान वनभूमि पर पट्टा दिया गया था। जिसमें लक्ष्मीनारायण, दूधनाथ, रतन सिंह, उदेराम, कुजबिहारी, राजेन्द्र कुमार, कलीराम, उधोराम व सुखदेव को पट्टे की भूमि मिली थी। पट्टे के कागजात में तत्कालीन कलेक्टर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास तथा वनमंडलाधिकारी के सील व दस्तखत भी हैं। इस दौरान तत्कालीन ग्राम सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। वर्तमान में चंदनिया


पट्टे की जमीन पर तालाब खुदाई

की महिला सरपंच हेमबाई व उसका पति इन पट्टाधारियों को बेदखल कराने में जुटे हुए हैं। पट्टे में मिले कागजात में जो हस्ताक्षर किए गए हैं, उसे फर्जी बताकर पट्टे की जमीन पर तालाब खुदवाने की तैयारी की जा रही है। इस मामले को लेकर आक्रोशित पट्टाधारी कलेक्टरों पहुंचे, जहां अपर कलेक्टर बिपिन मांझी से मुलाकात कर मामले की शिकायत की। अपर कलेक्टर श्री मांझी ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि शासन के नियमों के तहत उन्हें पट्टा दिया गया है। सरपंच अगर जबर्दस्ती करेगी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद ग्रामीण कलेक्टरों से लौट गए।


मेटल संबंधी उद्योग स्थापित करें - उज्ज्वल भविष्य बनाएं



मान.श्री दयालदास बघेल
मंत्री
वाणिज्य एवं उद्योग



मान.डॉ.रमन सिंह
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



मान.श्री बद्रीधर दीवान
अध्यक्ष
सीएसआईडीसी

मेटल उद्योगों की स्थापना का सुनहरा अवसर

राज्य शासन की योजनांतर्गत माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के करकमलों से दिनांक 8 अगस्त 2008 को शिलान्यास उपरान्त छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पो.लिमि. द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृत एवं प्रदूषण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त विकसित किए गए राज्य के प्रथम

मेटल पार्क फेस-1

रवांभाठा, जिला रायपुर

में फेरस एवं नान फेरस (मेटल) डाउनस्ट्रीम अप्रदूषणकारी सूक्ष्म / लघु उद्योगों एवं वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु भूमि/स्थान का आबंटन प्रारंभ

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु आरक्षित भू-खण्डों के लिये अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के एवं अन्य वर्ग के उद्योगी/संस्थान अनारक्षित भू-खण्डों के लिये दिनांक 16.02.2012 से दिनांक 02.03.2012 संध्या 5.00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र एवं नियम/शर्तें सी.एस.आई.डी.सी (मुख्यालय), रायपुर में उपलब्ध हैं। भूमि का आबंटन नियमानुसार किया जाएगा। नियम एवं शर्तें लागू

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें -
महाप्रबंधक, भू-आबंटन (मेटल पार्क)
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लि.
एलआरडीसी परिसर,पंडरी रायपुर, फोन-2583789,90, फैक्स-2583794
विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट www.csidc.in पर उपलब्ध है।

4876

विकास का वादा - मजबूत इरादा

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

न्यायालय तहसीलदार (नजूल) कोण्डगांव जिला कोण्डगांव छ.ग.

ईशतहार

रा.मा. क्र./अ-20(1)/2011-12
मौजा - विकासनगर कोण्डगांव
एतद् द्वारा सर्व साधारण निवासी नगर कोण्डगांव के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक पुष्पेन्द्र सिंह पिता स्व. जसवन्त सिंह जाति सिक्ख निवासी विकास नगर कोण्डगांव के द्वारा नगर कोण्डगांव के विकासनगर शीट अन्तर्गत नजूल भूमि शीट नं. 02 भू-खण्ड क्रमांक 69/1/1 में से क्षेत्रफल 480 वर्गफुट भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु स्थायी पट्टे की मांग बाबत नजूल अधिकारी कोण्डगांव को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिया गया है। आवेदन पत्र जांच कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी तिथि तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं परचात के दावा / आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया।
जारी दिनांक 04.02.2012
पेशी दिनांक 27.02.2012

तहसीलदार (नजूल) कोण्डगांव

(मुहर)

न्यायालय तहसीलदार (नजूल) कोण्डगांव जिला कोण्डगांव छ.ग.

ईशतहार

रा.मा. क्र./अ-20(1)/2011-12
मौजा -तहसीलपारा कोण्डगांव
एतद् द्वारा सर्व साधारण निवासी नगर कोण्डगांव के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक कोमल कुमार अरोरा पिता श्री सुरेंद्र कुमार अरोरा निवासी तहसीलपारा कोण्डगांव के द्वारा नगर कोण्डगांव के तहसीलपारा शीट अन्तर्गत नजूल भूमि शीट नं. 02 भू-खण्ड क्रमांक 588 क्षेत्रफल 3047 वर्गफुट भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु स्थायी पट्टे की मांग बाबत नजूल अधिकारी कोण्डगांव को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिया गया है। आवेदन पत्र जांच कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी तिथि तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं परचात के दावा / आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया।
जारी दिनांक 27.01.2012
पेशी दिनांक 27.2.2012

तहसीलदार (नजूल) कोण्डगांव

(मुहर)

संक्षिप्त खबरें

समीक्षा बैठक 10 को

अंबिकापुर, 8 फरवरी। सरगुजा कलेक्टर आर. प्रसन्ना की अध्यक्षता में 10 फरवरी को पूर्वाह्न 10.30 बजे से जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सांसद एवं विधायक मद में स्वीकृत कार्यों, सरगुजा विकास प्राधिकरण, एकीकृत कार्य योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

डॉ.यादव का लमगांव भ्रमण

अंबिकापुर, 8 फरवरी। राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र के चतुर्थ वर्ष के रावे प्रशिक्षण कार्यक्रम लमगांव लुण्डा जनपद में चल रहा है। इसके अंतर्गत डॉ.आर के यादव प्रमुख वैज्ञानिक का खेक्सा सब्जी के संदर्भ में लमगांव का भ्रमण किया गया। डॉ.आर. के यादव के द्वारा लमगांव के कृषकों को उत्पन्न हो रही समस्या को दूर करने के लिए तथा वैज्ञानिक तरीके से खेक्सा को खेती करने के लिए आवश्यक सलाह दिया। हमारे क्षेत्र में खेक्सा राज्य से आता है अधिकतम खेती करने के लिए तथा किसानों को खेक्सा की खेती के लिए उत्साहित करने के लिए डॉ.आर.के यादव के द्वारा ग्रामीणों को सम्भव सहायता देने का आश्वासन किया गया।

मैनपाट जनपद के कार्यक्रम अधिकारी की सेवा समाप्त

अंबिकापुर, 8 फरवरी। कलेक्टर एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक आर.प्रसन्ना ने जनपद पंचायत मैनपाट के संविदा कार्यक्रम अधिकारी शिव सागर तिवारी द्वारा मनरेगा के क्रियावन्धन में पर्याप्त रुचि नहीं लिए जाने के कारण एक माह का वेतन भुगतान करने हुए उनकी संविदा निरुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। कलेक्टर द्वारा मैनपाट यांत्रिकी सेवा उप संभाग सीतापुर के सहायक अभियन्ता आर.के. चन्द्रा को आगामी आदेश पर्यन्त जनपद पंचायत मैनपाट के कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है।

शिक्षाकर्मियों को 6 माह से वेतन नहीं

रामानुजगढ़, 8 फरवरी। विकासखंड अंतर्गत शिक्षा विभाग के शिक्षाकर्मियों को विगत 6 माह से वेतन भुगतान न होने के कारण अल्प वेतन कर्मचारियों को अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याओं से जुझना पड़ रहा है। वहीं विकासखंड शिक्षा अधिकारी विजय लहरे ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा करते हुए बताया कि नियमित कर्मचारियों का वेतन जमा हो चुका है तथा अल्प वेतन कर्मचारियों के 6 माह से वेतन भुगतान न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अल्प वेतन कर्मचारियों का वेतन पहले जता होना चाहिए जिससे शिक्षाकर्मियों के जीवन यापन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो सके। शिक्षाकर्मियों के विरल वेतन भुगतान की जानकारी देते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी.आर.ठाकुर ने बताया की एलाटमेंट न होने के कारण शिक्षाकर्मियों का वेतन भुगतान नहीं हो सका है। विभाग ने जिला को वेतन भुगतान के संदर्भ में पत्र लिखा है संभवतः जल्द ही शिक्षाकर्मियों का वेतन भुगतान हो जाएगा।